

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की छठी बैठक सम्पन्न

जीरो पॉवर्टी अभियान सर्वोच्च प्राथमिकता, सरकारी योजनाओं का समग्र लाभ प्रत्येक पात्र परिवार तक पहुँचे : मुख्यमंत्री

ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की विशेष टीम गठित कर पात्र परिवारों का अन्त्योदय कार्ड बनवाया जाए तथा आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास सहित सभी पात्र योजनाओं से चरणबद्ध रूप से जोड़ा जाए

मेरठ—हरिद्वार, विन्ध्य, विन्ध्य—पूर्वांचल तथा नोएडा—जेवर लिंक एक्सप्रेस—वे सहित सभी प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए 31 जुलाई तक भूमि उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, भूमि सम्बन्धी विषयों में सीधे भूमि—स्वामियों से संवाद स्थापित किया जाए

टेक्सटाइल पार्क के निर्माण कार्यों में तेजी लाते हुए इसे प्रदेश के वस्त्र एवं परिधान उद्योग के प्रमुख केन्द्र के रूप में विकसित किया जाए

आधारभूत संरचना के विकास के साथ जनसुरक्षा से जुड़े मानकों का कठोर अनुपालन सुनिश्चित किया जाए

सभी विद्युत फीडरों का विस्तृत विश्लेषण कर बिजली आपूर्ति, राजस्व वसूली, हानि—लाभ तथा ओवरलोड की स्थिति के आधार पर सुधारात्मक कार्ययोजना तैयार की जाए

बुन्देलखण्ड में औद्योगिक विकास की गति बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रशासनिक निर्णयों में अनावश्यक विलम्ब न हो

जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तावित कार्य स्थानीय आवश्यकताओं से सीधे जुड़े होते, परियोजनाओं की नियमित समीक्षा कर निर्धारित समय—सीमा में पूर्ण कराया जाए

किसानों को आधुनिक सिंचाई तकनीकों से जोड़ने के लिए समन्वित प्रयास किए जाएं

लखनऊ : 20 जुलाई, 2026

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज यहाँ अपने सरकारी आवास पर आहूत स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की छठी बैठक में प्रदेश में संचालित प्रमुख आधारभूत संरचना, औद्योगिक विकास, निवेश, जनकल्याण और सेवा वितरण से जुड़ी परियोजनाओं की व्यापक समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री जी ने जीरो पॉवर्टी अभियान को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए निर्देश दिए कि ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की विशेष टीम गठित कर पात्र परिवारों का अन्त्योदय कार्ड बनवाया जाए और उन्हें आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास सहित सभी पात्र योजनाओं से चरणबद्ध रूप से जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का समग्र लाभ प्रत्येक पात्र परिवार तक पहुँचना चाहिए।

बैठक में मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया कि जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत 12.50 लाख परिवारों का सर्वेक्षण किया गया है। इनमें लगभग 09 लाख परिवार

प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र पाए गए हैं, जबकि लगभग 05 लाख परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना के माध्यम से लाभान्वित किया जाना है। इसके अतिरिक्त, 6.67 लाख परिवारों के पास अभी आयुष्मान कार्ड उपलब्ध नहीं हैं। इनमें से लगभग 05 लाख लोगों का भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकरण हो चुका है, जबकि शेष पात्र परिवारों का पंजीकरण कराया जा रहा है। साथ ही, 10.60 लाख परिवारों के एक सदस्य को कौशल प्रशिक्षण से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया कि प्रदेश की प्रमुख एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए 88.45 प्रतिशत, झाँसी लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए 72.71 प्रतिशत, आगरा-लखनऊ-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए 63 प्रतिशत तथा जेवर लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए 59.35 प्रतिशत भूमि उपलब्ध करायी जा चुकी है।

मुख्यमंत्री जी ने मेरठ-हरिद्वार, विन्ध्य, विन्ध्य-पूर्वांचल तथा नोएडा-जेवर लिंक एक्सप्रेस-वे सहित सभी प्रस्तावित परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए सम्बन्धित जिलाधिकारियों को 31 जुलाई तक भूमि उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भूमि सम्बन्धी विषयों में सीधे भूमि-स्वामियों से संवाद स्थापित किया जाए। बैठक में लखनऊ नाइट सफारी परियोजना की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया कि गत 15 जुलाई को उच्चतम न्यायालय से इसके क्रियान्वयन की अनुमति मिल चुकी है। मुख्यमंत्री जी ने सभी औपचारिकताएँ शीघ्र पूरी कर परियोजना को समयबद्ध रूप से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए।

बैठक में ग्रेटर नोएडा में विकसित हो रहे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब एवं मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया कि 323 हेक्टेयर में से 301 हेक्टेयर भूमि प्राप्त हो चुकी है। लॉजिस्टिक पार्क के लिए 05 कम्पनियों ने पंजीकरण कराया है और आवंटन प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री जी ने परियोजना की सभी औपचारिकताएँ समयबद्ध ढंग से पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के लिए मॉडल बिल्डिंग बायलॉज की समीक्षा करते हुए कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को ध्यान में रखते हुए आवश्यक संशोधनों को शीघ्र अन्तिम रूप दिया जाए।

मुख्यमंत्री जी को लखनऊ में विकसित किए जा रहे टेक्सटाइल पार्क की प्रगति की समीक्षा के दौरान अवगत कराया गया कि परियोजना की आधारभूत संरचना तेजी से विकसित हो रही है। मुख्यमंत्री जी ने निर्माण कार्यों में तेजी बनाए रखते हुए इसे प्रदेश के वस्त्र एवं परिधान उद्योग के प्रमुख केन्द्र के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए। बैठक में उन्नाव की एक्वा ब्रिज परियोजना तथा कानपुर के बिनगवां स्थित 40 एम0एल0डी0 तृतीयक उपचार संयंत्र से पनकी ताप विद्युत संयंत्र को जलापूर्ति उपलब्ध कराने वाली परियोजना की भी समीक्षा की गई। उन्होंने लम्बित तकनीकी एवं प्रशासनिक

औपचारिकताएँ शीघ्र पूरी कर दोनों परियोजनाओं को समयबद्ध रूप से क्रियान्वित करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आधारभूत संरचना के विकास के साथ जनसुरक्षा से जुड़े मानकों का कठोर अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने सभी शासकीय एवं निजी मेडिकल कॉलेजों, चिकित्सा संस्थानों, जिला चिकित्सालयों तथा होटलों में वैध फायर एन0ओ0सी0 की समीक्षा करते हुए कहा कि जहाँ आवश्यकता हो, वहाँ तत्काल कार्यवाही कर अग्नि सुरक्षा मानकों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

बैठक में लखनऊ नगर निगम क्षेत्र में सीवर लाइन एवं मैनहोल के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन विद्युत लाइनों की स्थिति की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री जी ने सम्बन्धित विभागों को आपसी समन्वय से ऐसे सभी स्थलों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश की विद्युत वितरण व्यवस्था की समीक्षा करते हुए सभी विद्युत फीडरों का विस्तृत विश्लेषण कर बिजली आपूर्ति, राजस्व वसूली, हानि-लाभ तथा ओवरलोड की स्थिति के आधार पर सुधारात्मक कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने तकनीकी दक्षता, वित्तीय अनुशासन और उपभोक्ता सुविधा को समान प्राथमिकता देने पर जोर दिया। बैठक में बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) में भूमि अधिग्रहण की प्रगति की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बुन्देलखण्ड में औद्योगिक विकास की गति बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रशासनिक निर्णयों में अनावश्यक विलम्ब नहीं होना चाहिए।

मुख्यमंत्री जी ने डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फण्ड के उपयोग की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि इस निधि का उपयोग स्थानीय आवश्यकताओं और जनहित के कार्यों में पारदर्शिता एवं गुणवत्ता के साथ किया जाए। उन्होंने सांसद निधि एवं विधायक निधि से स्वीकृत विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तावित कार्य स्थानीय आवश्यकताओं से सीधे जुड़े होते हैं। उन्होंने जिलाधिकारियों को इन परियोजनाओं की नियमित समीक्षा कर निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कराने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री जी ने 'पर ड्रॉप मोर क्रॉप' योजना की समीक्षा करते हुए जल संरक्षण एवं सूक्ष्म सिंचाई को कृषि विकास की रणनीति का अभिन्न हिस्सा बनाने पर बल दिया। उन्होंने किसानों को आधुनिक सिंचाई तकनीकों से जोड़ने के लिए समन्वित प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री और डिजिटल संसाधनों तक बेहतर पहुँच उपलब्ध कराना है। उन्होंने इस कार्य को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए।